G.S. Paper III: Environmental pollution & degradation

***PM2.5 includes toxins like sulfate and black carbon*, which can *penetrate deep into the lungs or cardiovascular system. Air with more than 10 micro grammes per cubic metre of PM2.5 on an annual average basis is considered substandard.*

WHO report says over 90% of world breathing bad air

Nine out of 10 people globally are breathing poor quality air, the World Health Organization said Tuesday, calling for *dramatic action against pollution that is blamed for more than six million deaths a year.*

New data in a report from the UN's global health body "is enough to make all of us extremely concerned," Maria Neira, the head of the WHO's department of public health and environment, told reporters. *The problem is most acute in cities, but air in rural areas is worse than many think*, WHO experts said.

Tuesday's report was based on data collected from more than 3,000 sites across the globe. It found that "92 percent of the world's population lives in places where air quality levels exceed WHO limits". The data focuses on *dangerous particulate matter with a diameter of less than 2.5 micrometres, or PM2.5.*

The WHO has estimated that more than six million deaths per year are linked to exposure to outdoor and indoor air pollution. Data is more solid for outdoor pollution, which is blamed for more than three million fatalities annually.

But indoor pollution can be equally as harmful, especially in poorer developing world homes where cooking often involves burning charcoal. Nearly 90-percent of air pollution-related deaths occur in low and middle-income countries, the WHO said.

Southeast Asia and the Western Pacific region—including China, Malaysia and Vietnam—are the hardest hit, the data showed.

G.S.Paper III: Science & Technology: developments & their applications & effects in everyday life

** लीघ सिंड्रोम बीमारी माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए के माध्यम से बच्चों में पहुंच जाती है। इस बीमारी से व्यक्ति का नर्वस सिस्टम प्रभावित हो जाता है।

** हर कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया होता है जिसका काम कोशिका को ऊर्जा प्रदान करना होता है.

डीएनए मां-बाप का, जेनेटिक कोड डोनर का: पहली बार तीन लोगों के योगदान से पैदा हुआ बच्चा (बीबीसी हिंदी)

विज्ञान शोध पत्रिका न्यू साइंटिस्ट के अनुसार तीन अभिभावकों वाला दुनिया का पहला बच्चा जन्म ले चुका है। पांच महीने के इस बच्चे में उसके ***मां-बाप के पारंपरिक डीएनए के अलावा एक अन्य डोनर के जेनेटिक कोड हैं।*** इस बच्चे का जन्म मेक्सिको में हुआ था। इस पद्धति से बच्चों के प्रजनन के आलोचकों का कहना है कि मनुष्य अब "ईश्वर की तरह" पेश आ रहा है। जबकि इस समर्थकों का कहना है कि इस तरह जेनेटिक बीमारियों से पीड़ित दंपति भी स्वस्थ बच्चा प्राप्त कर सकते हैं। न्यू साइंटिस्ट के अनुसार बच्चे के माता-पिता जॉर्डन के रहने वाले हैं। बच्चे में तीसरे व्यक्ति के जेनेटिक कोड डालने का काम अमेरिकी विशेषज्ञों ने किया।

बच्चे की मां को लीघ सिंड्रोम नामक जेनेटिक बीमारी है। कुछ महिलाओं के माइटोकॉन्ड्रिया में आनुवांशिक दोष पाए जाते हैं जिससे उनके बच्चों में भी वही दोष हो सकता है.इस विकार को लेह सिंड्रोम कहा जाता है. ये पैदा होने वाले बच्चे के लिए

Prepare IAS

इसे कोशिका का पॉवर हाउस भी कहा जाता है.

** आम डीएनए के उलट माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए मनुष्य की कोशिका ऊर्जा प्रदान करते हैं।

** कई वैज्ञानिक इस पद्धति से पैदा होने वाले बच्चों को "तीन अभिभावकों वाले बच्चे" कहने पर आपत्ति जताते हैं। ऐसे वैज्ञानिकों का कहना है कि इन बच्चों में महत्वपूर्ण डीएन दो लोगों के ही होते हैं ऐसे में उन्हें 'तीन लोगों का बच्चा' कहना उचित नहीं है।

G.S.Paper III: Environmental conservation.

**Paris Agreement:

It was materialized at the 21st Conference of Parties of the United Nations Framework Convention on Climate Change—*requires 55 countries accounting for at least 55% of global greenhouse gas emissions to ratify it in order for it to come into force.*

It aims to contain the increase in earth's temperature to 2 degrees Celsius, and if possible 1.5 degrees Celsius, above pre-industrial levels

India,though third in terms of total emissions, it ranks 140th globally in terms of per capita emissions.

जानलेवा साबित हो सकती थी.महिला खुद तो स्वस्थ है लेकिन उसके दो बच्चे, एक छह वर्षीय लड़की और एक आठ महीने का लड़का पहले ही इस बीमारी के कारण मर चुके हैं।

न्यूयॉर्क के न्यू होप फर्टिलिटी क्लिनिक के डॉक्टर जॉन झांग बताते हैं कि मां के अंडाणु से न्यूक्लियस लेकर उसमें डोनर के अंडाणु में डाल दिया जाता है। डोनर के अंडाणु से उसका न्यूक्लियस पहले ही निकाल दिया जाता है लेकिन उसमें डोनर के स्वस्थ माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए मौजूद रहते हैं। मासट्रिस्ट यूनिवर्सिटी के जीनोम सेंटर के प्रोफेसर बर्ट स्मीट्स ने द इंडिपेंडेंट से कहा, "आखिरकार माइटोकॉन्ड्रियल दान के बाद ***माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए म्यूटेशन से दुनिया के पहले बच्चे*** का जन्म हो गया। ब्रिटेन के न्यूकैसल ग्रुप ने पहले ही दिखा दिया था कि ये तरीका सुरक्षित है और अस्पतालों में इसकी सुविधा प्रदान करना संबंधित देश के कानूनों और समय की बात है।"

A new greenprint on climate change

(livemint.com)

On 2 October a year ago, India moved to allay any international scepticism about its commitment to combating climate change by announcing *its Intended Nationally Determined Contributions (INDCs).* India is to reduce the emissions intensity of its gross domestic product by 33-35% by 2030 from 2005 levels, it said in an announcement. It's a hurried move—but because of diplomatic compulsions, New Delhi has chosen to couch pragmatism in the symbolism of Gandhi's birth anniversary.
New Delhi had gone slow so far—but with the threshold likely to be reached without it in October, and the possibility thereafter of being cast in an obstructionist role diplomatically, it has understandably changed track.

But India still has good reason to be wary at the negotiating table because of three reasons. First, too much focus on incremental pollution by developing countries shifts the public attention away from the historical damage done by the developed countries during their years of rapid economic growth. Second, the per capita carbon footprint of India is still very low by global standards. Third, India needs coal as part of its energy mix right now, until new technologies emerge.

By retaining the "common but differentiated responsibilities" clause in the Paris Agreement, the world has acknowledged Indian concerns. Undue pressure is already being exerted on India as one of the largest polluters of the world. However, with its large

Prepare IAS

Suggested Question: What should be India's strategy for combating climate change along with achieving targets of Paris agreement?

coastline susceptible to rising sea levels and a population suffering from the visible consequences of climate change, such as heat waves, pollution and failed monsoons, the country couldn't have argued for its rights to development beyond a point. It therefore made a calculated choice considering its long-term costs. It embraced the cause of climate change but with a caveat—the availability of global finance and performance of other nations. The cabinet decision, which came on Wednesday, implicitly emphasizes that the onus is on developed nations to fund and transfer technology to developing nations, besides making efforts to meet their domestic commitments.

G.S. Paper II: Issues relating to development & management of Social Sector

महाराष्ट्र में मराठा आंदोलन से मिले खतरनाक संकेत (दैनिक भास्कर)

पहले गुजरात फिर हरियाणा और अब महाराष्ट्र में उभरे शासक वर्ग के आंदोलन ने जहां राज्य सरकार की नींद हराम कर दी है वहीं भारतीय लोकतंत्र की तमाम अवधारणाओं पर प्रश्न-चिह्न खड़ा कर दिया है। अगर गुजरात में पटेलों ने आरक्षण के लिए राज्य सरकार की चूलें हिला दीं तो हरियाणा में जाटों ने पूरे राज्य को युद्ध क्षेत्र में बदल दिया था। अब वही स्थिति महाराष्ट्र में है। यह जानते हुए कि मराठों ने जो मांगें की हैं उसमें सिर्फ *कोपर्डी दुष्कर्म कांड पर कार्रवाई करने के अलावा कोई और मांग मानना असंभव है*, कांग्रेस, राकांपा, भाजपा और शिव सेना समेत सारे दल इस आंदोलन के साथ खड़े हैं।

** राजनीतिक दलों और सामाजिक संगठनों को इस दिशा में काम करना होगा कि सामाजिक न्याय और विकास के जिस सिद्धांत पर हमारा लोकतंत्र चल रहा है उसका लाभ सबको मिले और उससे लगातार सामाजिक तनाव कम करने में मदद मिले।

मौजूदा संवैधानिक ढांचे के भीतर न तो 50 प्रतिशत से ज्यादा आरक्षण संभव है और न ही मौजूदा स्थितियां संसद से 1989 में पारित अनुसूचित जाति और जनजाति अत्याचार विरोधी कानून को खत्म करने की इजाजत देती हैं। *जहां कांग्रेस-एनसीपी की तरफ से मराठों को दिए आरक्षण को हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है वहीं बाबा साहेब आंबेडकर की 125वीं जयंती पर दलितों को न्याय दिलाने का संकल्प जताने वाले राजनीतिक दल कैसे उस कानून को खत्म करेंगे जो दलितों को कहीं राहत देता है।* इसके बावजूद राजनीतिक दल मराठों की 22 प्रतिशत आबादी और उसका आक्रोश देखकर इतने घबरा गए हैं कि वे उन दलितों की ओर से मुंह मोड़ने लगे हैं, जिनकी आबादी महज 11 प्रतिशत है। राजनीतिक दल न्याय अन्याय और सही-गलत का आग्रह भी छोड़ बैठे हैं।

** Here the *battle is not for justice to the downtrodden but a search for consolidation and privilege*. Quotas and reservation no longer embody a search for justice, but an interest group politics where the powerful seek to accumulate more power.

निश्चित तौर पर जिस दलित ने अहमदनगर जिले के कोपर्डी गांव में मराठा नाबालिग लड़की से दुष्कर्म और हत्या का अपराध किया उसे कानून के मुताबिक सजा मिलनी चाहिए। ***किंतु सारे दलित समुदाय को दोषी मानकर उसे मिले सुरक्षा के विशेषाधिकारों को छीनने की मांग गैर-वाजिब है।*** मराठा लंबे समय से शासक रहे हैं और उनकी सामाजिक हैसियत ऐसी कमजोर नहीं है कि उन पर अत्याचार की नियमित घटनाएं हों। आज जिस तरह से शासक वर्ग में विद्रोह की भावना उमड़ रही है वह पूरे लोकतंत्र के लिए घातक संकेत दे रही है।

Prepare IAS

A story to two caste struggles (The Hindu)

** The logic of the scripts and the nature of political dramas is radically different. *First, the Dalits' protests for rights have the character of an appeal. They are seeking to go beyond deprivation. The upper caste protests convey a sense of threat, of aggression and violence. For Dalits, democracy is a value; for upper castes it appears relevant as long as it sustains them instrumentally in power.*

*** The marginals speak the language of suffering, deprivation and pain. The dominant castes utter the language of privilege, of consolidation.*

***Two major demandsof Marathas-* The first was a demand to repeal the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Act, and the second a demand for a greater share in the reservation.

The Dalit fighting for rights still upholds the universality of citizenship. The dominant castes insisting on consolidating their privileges reduce democracy to the worst kind of parochial politics.

Politics cannot be studied as a mere set of facts as if they are little nuggets to be polished and examined on their own. Politics needs frameworks which provide ways for interpretation and understanding. One senses the need for this when one watches the sudden explosion of upper caste agitations. An ethnography of these demonstrations alone is not enough. One has to see them as statements of values, of the manner in which democracy is seen and assessed.

One can see three *visions of democracy contesting and overlapping with each other*.

The early socialist vision saw democracy as a place where rights to quality were worked out, where the marginal and minority groups used the democratic process to be empowered as citizens. Such a vision is captured in the careers of B.R. Ambedkar and Ram Manohar Lohia. The second kind of vision inaugurated after the Bharatiya Janata Party came to power was a majoritarian vision, where electoralism was a consolidation of numbers. The transition from democracy as a value to a fact of demography becomes obvious here. There is a third kind of contest emerging where democracy, like the market, becomes a competitive game, where right loses to might and democracy becomes a fragile Hobbesian word.

There is a politics of anxiety played out by the upper class who see democracy not as a framework of universal values but as a basis for consolidating a parochial world. The contrast is stark between a Dalit or tribal battling for rights and the demands of upper castes such as Patels, Jats and Marathas.

The body languages of the two dramas are different. One acts as a shareholder threatening to sell his shares or dismiss the directors if the firm fails to show profit. *Rights meet a mentality of consolidation. One creates a politics of consensus, protest and persuasion, the other engages in a game of threat, preferring democracy as a zero-sum game. The Dalit fighting for rights still upholds the universality of citizenship. The dominant castes insisting on consolidating their privileges reduce democracy to the worst kind of parochial politics, a bullyboy spectacle which makes*

Prepare IAS

democracy appear empty and ironic. One sees this drama enacted with ruthless clarity in the recent protest of Marathas.

Between the appeals and protests of Dalits and tribals and the arrogant demands for continued dominance lies the new problematic form of democracy in India. Democracy as a way of life is threatened by electoral democracy as a rule game. First, majoritarianism threatens the pluralism of Indian democracy. Second, dominance of castes in the system threatens any hope for rights, for a more equalitarian system. The challenge of the future lies in how democracy reinvents itself to handle these two contradictions. Otherwise, India faces the final irony — that of democracy as a mechanism quietly corroding the institutional values of democracy as a value system.

Paper III: Major crops, cropping patterns in various parts of the country

** केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्रालय के अंतर्गत आने वाली जीन संवर्धित **अभियांत्रिकी मूल्यांकन समिति (जीईएसी)** की एक उपसमिति ने जीएम सरसों पर अपनी रपट अगस्त में सरकार का सौंपी थी, जिसमें जीएम सरसों को अधिक पैदावार वाली और पर्यावरण तथा मानव स्वास्थ्य की दृष्टि से सुरक्षित फसल बताया गया है।

** में जीएम सरसों की इस किस्म पर खरपतवार नाशक का असर नहीं पड़ने की बात कही है। यानी **यह फसल 'हर्बीसाइड टॉलरेंट' होगी**। उन्होंने कहा इसका एक खतरा यह है कि किसान ज्यादा मात्रा में रसायनों का प्रयोग करने लगेंगे, जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होगा।

जीएम सरसों के 'हर्बीसाइड टॉलरेंट' होने से खेत की उर्वरता बुरी तरह प्रभावित होगी। साथ ही अधिक मात्रा में रसायनों के प्रयोग से फसलों की गुणवत्ता भी उच्चकोटि की नहीं रहेगी

जीएम सरसों को मंजूरी के खिलाफ किसानों की आंदोलन की धमकी (बीबीसी हिंदी)

देश के कई किसान संगठनों ने जीएम सरसों की खेती को मंजूरी देने के प्रस्ताव का विरोध करते हुए इसके खिलाफ 2 अक्टूबर को गांधी जयंती से आंदोलन शुरू करने की चेतावनी दी है। इन संगठनों ने सरकार ***से मांग की है कि जीएम सरसों पर जारी विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट पर सार्वजनिक टिप्पणी के लिए अधिक समय दिया जाए और कोई निर्णय जल्दबाजी में नहीं लिया जाए।***

मजदूर किसान शक्ति संगठन के संस्थापक निखिल डे ने जीएम फसलों का विरोध करते हुए कहा, 'सरकार का यह कदम प्रकृति को बदलने जैसा प्रयास है, जो मानव को पीढ़ियों तक नुकसान पहुंचाएगा। हम सख्ती से इसका विरोध करते हैं। सरकार ने जीएम सरसों वाली रपट पर सार्वजनिक टिप्पणी के लिए बहुत कम समय रखा है। इसके लिए कम से कम 120 दिन तक का समय देना चाहिए।'

आशंका है कि जीएम सरसों की खेती को मंजूरी दी जाती है तो सरसों **की खेती वाले क्षेत्रों में शहद का कारोबार बुरी तरह प्रभावित होगा।** उन्होंने कहा कि अकेले *उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर इलाके से सालाना करोड़ों रुपये का शहद निर्यात होता है पर जीएम सरसों आने के बाद उन पर मधुमक्खियां कम आएंगी।* मलिक ने कहा कि जीईएसी के वैज्ञानिकों ने अपनी रपट

कपास में भी जीएम खेती की मंजूरी दी गई थी। पिछले साल पंजाब के किसानों ने काफी मात्रा में इसकी पैदावार की, लेकिन उसके पौधे कुछ निश्चित लंबाई के बाद बढ़ना बंद कर देते हैं और ज्यादा पैदावार नहीं हो पाती। पिछले साल के अनुभवों के बाद इस साल पंजाब के किसानों ने गैर-जीएम कपास की बुवाई ही की है।

उल्लेखनीय है कि अभी तक देश में सिर्फ कपास के ही जीन संवर्धित (जीएम) बीजों के व्यावसायिक इस्तेमाल को मंजूरी दी गई है। यदि सरसों में भी जीएम बीज के इस्तेमाल की मंजूरी मिलती है तो यह देश में जीएम की पहली खाद्य फसल होगी। जीएम खाद्य उत्पादों के तहत बीटी बैंगन उगाने की अनुमति

Prepare IAS

2010 में दी गई थी, लेकिन विरोध के कारण तत्कालीन पर्यावरण मंत्री जयराम रमेश ने इस पर रोक लगा दी थी।

Paper III: - Indian Economy & issues relating to planning, mobilization of resources, growth, development & employment

- Govt budgeting

** The recent passage of the Goods and Services Tax (GST) Bill, which will put in place a uniform indirect tax regime in India, is a landmark achievement for the Narendra Modi government.

** GST, once implemented, will, for the first time in India's history, unify the nation into a common economic market, obviating the need for goods to be taxed each time they cross a state border.

Suggested Question: How GST will likely have impact on India's international trade and on its trade strategy?

Govt unveils draft rules on GST returns (Business Standard)

The centre on Tuesday released draft rules that establishments have to follow for filing returns and claiming refunds under the goods and services tax (GST). The draft rules mandate taxpayers to file monthly tax returns. Those opting for the compounding scheme (traders with an annual revenue of up to Rs50 lakh can pay a flat tax and escape the compliance requirements) need to file their tax returns quarterly.

Businesses will also have to furnish information on the profit or loss incurred in the GST return form, which could prove to be onerous.

The refund rules say that the tax officer will have to process the application for refund within 15 days of the claim being filed. Further, in cases where the taxpayer has an impeccable record—no prosecution for any tax evasion offences in the past five years and a good compliance rating—will be eligible for provisional refund within seven days. Businesses located in special economic zones will have to pay GST upfront and then claim refunds, in a move that could impact IT firms.

All this, along with the three draft rules on registration, tax payment and invoice released on Monday, will be finalized on 30 September in the GST council's second meeting.

GST and Indian trade (The Hindu)

The GST council, which will oversee the GST regime, is currently in deliberations over its own procedures and over the appropriate tax rate to prevent revenue shortfalls. GST will affect all aspects of business in India, from decisions on investment location and product pricing to logistics and supply chain optimization; it is being widely applauded as a crucial reform that will facilitate India's development trajectory.

GST is a development that comes at a challenging time in the external environment for India. Global growth has slowed. Many major economies in the world face economic and political challenges with uncertain resolution. With the British vote to exit the European Union, the EU now confronts the possibility of a disintegration, with a larger collapse of the Eurozone in the coming years remaining a real, even if unlikely, possibility. Japan, once a driver of global growth, now lies dormant and is struggling to revive itself. China, after two decades of extraordinary growth, appears to

PrepareIAS

be slowing down. The US is going through a divisive presidential election that has seen its candidates adopt threatening postures towards international trade, especially with lower-income countries, and towards the world trade system more generally. To achieve improvements in trade performance in this environment will clearly be difficult.

Integrating with the global economy (livemint)

Paper III: Effects of liberalization on the economy, changes in industrial policy & their effects on industrial growth

Suggested Question : There is anti-globalization mood in Industrialised countries like Brexit, the appeal of Donald Trump, and the rise of nationalist anti-immigration parties in Europe, According to you how it affect India's strategy of economic growth?

** Business has a big role to play in building support for trade agreements. Unfortunately, Indian business has been more concerned with ensuring that protection to domestic producers is not diluted and less with getting access to export markets.

Singapore's deputy prime minister, Tharman Shanmugaratnam, in the first Niti Aayog lecture addressing cabinet ministers and senior officials, said *no country has been able to achieve rapid growth without integrating with the global economy and India should integrate more fully than we have*. He recognized that our size, diversity and democratic polity imposed special constraints, and we had done well given these constraints. But we cannot expect to achieve 8-10% growth if we continue with business as usual. Putting it colourfully, he said we cannot just go on scoring singles—we have to start hitting fours and sixes.

To integrate with the global economy, *we need to increase our competitiveness.* This calls for some bold reforms to improve the quality of infrastructure and logistics, greater ease of doing business (covering government/business interface in the Centre and states), a financial system that serves small- and medium-sized firms, skill development, labour market flexibility, etc. It also calls for new initiatives in our external engagements, some of which are discussed below.

Reducing import duties

Import duties were reduced very substantially after 1991, but they need to be reduced further. In 1997-98, then finance minister P. Chidambaram had set the target that import duty rates should be reduced to Asean (Association of South-East Asian Nations) levels by 2000. Sixteen years after that target date, our import duties remain significantly above the Asean level.

Now that we have signed a free-trade agreement with Asean, retaining higher duties than those in Asean will raise our domestic cost structure, making it difficult to compete with the low duty imports that will be allowed from Asean. It will also reduce the competitiveness of our exports to those markets. We should move to lower most non-agricultural duties to reach an average of around 5% in two years. This will also help tackle the problem of duty inversion, which has been a source of much complaint. *Those who worry about an adverse effect on the economy, should recall that duties were reduced much more sharply after 1991, with considerable benefit.*

Prepare IAS

Duty reduction may be resisted because of revenue loss. However, contemporary best practice holds that import duties should not be viewed as a revenue source. Whatever indirect tax revenue we need should come from the non-distortionary GST (goods and services tax), which is now clearly on the horizon.

We also need to rethink our approach to trade negotiations. We have traditionally preferred trade negotiations within the multilateral World Trade Organization (WTO) framework, viewing regional trade agreements as distortionary. We were also committed to the Doha Round as a "single undertaking". These perfectly reasonable positions have become unsustainable after the Doha Round was effectively abandoned in Nairobi in 2015.

One reason for the abandonment of Doha is that industrialized countries, seeing the changes in the structure of world trade with the growing importance of global value chains, lost interest in obtaining tariff reductions and became much more interested in "deeper integration" of behind the border standards on issues such as labour, environment, protection of intellectual property, competition policy, etc. This could not be pursued within the tariff-based negotiations in the WTO, so they shifted their focus on pursuing "mega regional agreements" such as the Trans-Pacific Partnership (TPP) involving the US, Japan, Korea and some developing countries, and the Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP) involving the US and the European Union (EU). These mega regionals were negotiated among a small group of industrialized countries, and it was expected that they would then be opened to other countries to join if they were willing to accept the terms of the agreement. An unstated purpose of the exclusionary approach was to keep China out of the initial negotiations and offer entry only after the terms were set.

The TTIP has run into roadblocks and no early resolution is expected given the anti-globalization mood in Europe. The TPP has been signed, but not yet ratified by the US, and opinions vary on whether it will be ratified soon. However, we should note that China is widely reported as preparing itself internally to meet the TPP standards, so that it keeps open the option of joining if it wishes. If China does join the TPP, it will be a very powerful trade block, and staying out of it will put us at a severe disadvantage.

More immediate decisions are needed in the context of our stalled negotiations with the EU and the ongoing process in the Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP). A successful outcome would send a very strong signal of India's willingness to engage with the global community. In the case of RCEP, it is also a geopolitical signal of our willingness to walk the talk on "Act East". Trade negotiations are complex exercises in which no country gets everything it wants. There are inevitable compromises at the last stage, when our negotiators may have to concede on some points, in order to gain on others. It is important to prepare public opinion not to regard every concession as a failure.

There are some plurilateral negotiations being pursued by the industrialized countries within the WTO, e.g. trade facilitation, zero tariff on environmental goods, information technology agreement (ITA) II, government procurement. These are stand-alone agreements delinked from the Doha Round as a "single undertaking". We have recently signed up on trade facilitation, but have been unwilling to join the other negotiations, possibly because we regarded them as distractions from the Doha Round as a single undertaking. Now that the Doha Round is dead, we need to take a considered view

Prepare IAS

on whether we should join. Here again we should not assume that we cannot increase our competitiveness.

The Trade in Services Agreement (Tisa) is a plurilateral agreement outside WTO being negotiated by the US, EU and several countries, including some developing countries. We have a comparative advantage in high-end services, but we are not part of Tisa. When Doha was still alive, it was possible to believe that a multilateral agreement on services would be negotiated in that forum. Since that is no longer possible, we need to address the question of whether we should be part of Tisa. One of our problems in services is that we have been fixated on Mode 4, which involves movement of persons. This is in our interest, but as long as unemployment remains high in industrialized countries, it is unlikely that we will get any comfort in this area. We should, therefore, be realistic in our expectations.

Two other elements of policy which have an impact on our external engagement are taxation and investor protection. The fact that MNCs will still be tempted to shift profits to tax havens which have exceptionally low tax rates ,and the Organisation for Economic Co-operation and Development is working on ways to counter such base erosion and profit shifting. We should support this effort and act in accordance with internationally agreed best practice. But we should not go beyond the international consensus.

Investor protection through bilateral investment treaties is another critical dimension of engagement. We do not have a treaty with the US and have recently started negotiation. The US is seeking to introduce many new features, including on intellectual property rights, which could pose problems. We too have modified our earlier template by excluding international arbitration until investors have exhausted the remedies offered by the domestic judicial process. This may have been reasonable if our domestic process was speedy, but it is not. The negotiations with the US will give a good idea of whether there is common ground. If we come to an agreed position vis-à-vis the US, we can reasonably push it with other countries. However, we should avoid any unilateral abrogation of existing treaties.

**multinational corporations (MNCs) operate across the world in different parts of the value chain gives them the opportunity to shift profits to lower tax destinations. The incentive is particularly high in India because corporate tax rates are much higher than in other countries. We should align our corporate tax rates with those of other countries.

To summarize, it is to our advantage to deepen engagement with the global economy and we must do what is necessary, domestically and externally, to facilitate the process. The suggestions above provide a core set of initiatives in external economic policy. Perhaps the government should set up a high-level committee, including representatives of business, trade economists, and legal experts in trade and investor protection, to make specific recommendations for action.

Prepare IAS

Paper 3 Topic: Indian Economy and issues relating to planning, mobilization of resources, growth, development and employment.

India improves in Global Competitiveness Index

India fastest riser, moves up 16 spots to 39th rank in the World Economic Forum's Global Competitiveness Index

India's ranking in the Global Competitiveness Index for 2016-17, released by the World Economic Forum (WEF), improved 16 places to 39, making it the fastest riser up the ranks among 138 countries surveyed.

India's competitiveness improved across the board, particularly in goods market efficiency (60), business sophistication (35) and innovation (29). WEF said recent reform efforts by the government have concentrated on improving public institutions (up 16 places), opening the economy to foreign investors and international trade (up 4), and increasing transparency in the financial system (up 15).

India still needs to cover a lot of ground, the WEF said, citing labour market deficiencies, large, public enterprises that reduce economic efficiency, especially in the utilities sector and the financial market. Lack of infrastructure remains a critical bottleneck, the report said.

PrepareIAS

9/28/2016 Live Hindustan

Live हिन्दुस्तान .com

नई दिल्ली, एजेंसी
First Published:28-09-2016 11:57:21 AM
Last Updated:28-09-2016 11:57:21 AM

भारत दुनिया में 39वीं सबसे प्रतिस्पर्धी अर्थव्यवस्था : डब्ल्यूईएफ

भारत विश्व आर्थिक मंच 'डब्ल्यूईएफ' के वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक में 16 अंक की छलांग लगाकर 39वें स्थान पर पहुंच गया है। कारोबारी जटिलताओं तथा वस्तु बाजार दक्षता में सुधार से भारत की रैंकिंग सुधरी है। लगातार आठवीं बार स्विटजरलैंड सबसे अधिक प्रतिस्पर्धी अर्थव्यवस्था बना है।

भारत में बाजार का बदलता रुख

साल	भारत वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक	कुल देश
2016-17	39 ▲	138
2015-16	55 ▲	140
2014-15	71 ▼	144
2013-14	60 ▼	148
2012-13	59	144

भारत का प्रदर्शन	रैंक 2015-16	रैंक 2016-17	
बुनियादी आवश्यकताएं	80	63	▲
संस्थाएं	60	42	▲
आधारभूत संरचनाएं	81	68	▲
मैक्रोइकॉनोमिक एनवायरनमेंट	91	75	▲
स्वास्थ एंव प्राथामिक शिक्षा	84	85	▼
दक्षता सुधार	58	46	▲
उच्च शिक्षा एंव ट्रेनिंग	90	81	▲
माल बाजार दक्षता	91	60	▲
श्रम बाजार दक्षता	103	84	▲
वित्तीय बाजार विकास	53	38	▲
तकनीकी तत्परता	120	110	▲
बाजार आकार	3	3	◀▶
नवाचार और परिष्कार कारक	46	30	▲
व्यापार परिष्कार	52	35	▲
नवाचार	42	29	▲

Source Global Competitiveness Index

G.S.Paper-II: *India & its Neighbourhood*: relations

** South Asia sought to evolve, much in the manner that the Association of South East Asian Nations had stitched itself together two decades earlier.

**. At a moment when SAARC was being formed in the mid-1980s, Pakistan set up the Economic Cooperation Organisation (ECO) with Iran and Turkey. After the collapse of the Soviet Union, the Central Asian states joined the ECO.

** The BBIN (*Bangladesh, Bhutan, India and Nepal*) framework was seen by many as heralding the era of 'SAARC Minus One'.

** If the Look East Policy aimed to integrate India with Asia, Delhi also helped create a regional forum called the BIMSTEC (Bay of Bengal Initiative for Multi-Sectoral Technical and Economic Cooperation). Although it dates back to 1997, the forum that brings five South Asian countries (Bangladesh, Bhutan, India, Nepal and Sri Lanka) together with two south east Asian countries (Burma and Thailand) has remained dormant.

Prepare IAS
urrent affairs Sep.24-30,2016

SAARC minus one (Indian express)

Prime Minister Narendra Modi's decision to skip the South Asian summit in Islamabad next month is, in essence, about the deteriorating relationship with Pakistan. It also underlines the growing irrelevance of the South Asian Association of Regional Cooperation for India's regionalism. Irrespective of India's future relations with Pakistan, the Modi government's search for alternatives to SAARC will now acquire a new momentum.

For too long, India had conflated its regionalism with SAARC that was established three decades ago at the initiative of Bangladesh. While Delhi and Islamabad were both wary of the move in the mid-1980s, *it was the inward economic orientation of the Subcontinent that limited possibilities for regional cooperation.* As the Subcontinent launched economic reforms in the 1990s, regional integration appeared a natural consequence waiting to happen. As the South Asian states opened up to the world, it seemed sensible to connect with each other. But that was not how it turned out.India, on its part, inched towards accepting regionalism as an economic and political necessity. The SAARC, in turn, began to emphasise trade liberalisation, regional connectivity and trans-border economic projects.

As SAARC developed new proposals and agreements in favour of preferential trade, free trade, road and rail connectivity and cross-border energy projects, it became clear that Pakistan was the camel that slowed down the pace of the South Asian caravan. More accurately, it was the Pakistan Army headquartered in Rawalpindi that exercised the veto. It was not that the Pakistan army was against the idea of regional cooperation. More recently, Rawalpindi has become the champion and guardian of the trans-border China-Pakistan economic corridor.

Rawalpindi's problem was with the idea of economic integration with India. Neither the initiatives of SAARC, nor the Indian appeals, were capable of changing this. China and the United States, two of Pakistan's best friends, often tried nudging Rawalpindi to take a more positive view of economic cooperation with India. Civilian leaders at the national as well as the provincial level in Pakistan have long sought greater cooperation across the borders. But resistance of Pakistan's 'deep state' was insurmountable.Two most recent examples have been the talks on trade liberalisation and cross-border trade in energy during the last years of the UPA government. Islamabad pulled back just when the agreements were ready for signature. Pakistan also walked away from

Prepare IAS

agreements on road connectivity after they were presented to the heads of government at the last SAARC summit in Kathmandu in November 2014.

In the past, Delhi simply shrugged its shoulders. Although it was clear that the SAARC caravan was going nowhere with Pakistan, it seemed there was little that India could do. PM Modi, however, took a different track. At the Kathmandu summit, he called for a two-speed SAARC. Rather than let one country take the entire region hostage, Modi suggested, those who are ready for integration should move ahead. *As a result, Bangladesh, Bhutan, India and Nepal got together soon after the Kathmandu summit to implement the motor vehicle agreement.*

The BBIN framework was seen by many as heralding the era of 'SAARC Minus One' and hostile to Pakistan. The BBIN, however, was very much part of the SAARC framework. The SAARC charter allows two or more countries of the forum to embark on what is called 'sub-regional cooperation'. It was a policy instrument that was long available to policymakers in Delhi but remained unutilised. Delhi could also complement its sub-regional initiative with trans-regional outreach.

The Modi government is now eager to re-energise the BIMSTEC forum. As part of that commitment, it has invited the BIMSTEC leaders to join the BRICS leaders at the Goa summit next week. Modi's meetings with the BIMSTEC leaders present a major opportunity to demonstrate that the meltdown of SAARC does not mean India is giving up the ambitions of its neighbourhood first strategy. One thing that the PM, who never misses an opportunity to coin a new acronym, might want to do is to give the BIMSTEC a more attractive name. The Bay of Bengal Community? BOBCOM, anyone?The turn to the east, however, does not resolve India's Pakistan problem in promoting economic cooperation with Afghanistan. Rawalpindi is dead set against letting Indian goods move overland to Afghanistan, despite fervent appeals from Kabul and an occasional entreaty from Washington. With no physical access to Afghanistan, Delhi needs to find creative ways to deepen bilateral economic engagement with Kabul bilaterally and through trilateral cooperation with other partners like Tehran.

Pakistan is free to choose its partners. It has consciously embraced China as the strategic economic partner; Rawalpindi believes that restoring historic economic connectivity with India is a threat to Pakistan. India can't compel Pakistan to join the project of South Asian integration. Instead of bemoaning that fact, Delhi must devote itself to bilateral, sub-regional and trans-regional cooperation with our neighbours, all of whom except Pakistan want India to do more. SAARC may be headed to the mortuary. But India can easily catch a new wind in its regional sails.

सार्क और उसकी भावना (लाइव हिंदुस्तान)

भारत ने मंगलवार को जिस तरह से आतंकवाद के मुद्दे पर पाकिस्तान को अलग-थलग करने की रणनीति दिखाई, तभी लगने लगा था कि नतीजे ऐसे ही आएंगे। भारत ने न सिर्फ पाकिस्तान की जमीन पर होने वाले सार्क देशों के सम्मेलन से अपने को अलग रखने का फैसला लिया, वरन उसी वक्त उरी हमले में उसकी संलिप्तता के पुख्ता सबूत भी उसे सौंपे। पाकिस्तान की नीति और नीयत पर यह दोहरी चोट थी। *भारत के इस फैसले के तत्काल बाद बांग्लादेश, भूटान और अफगानिस्तान ने भी सार्क सम्मेलन से अपने को अलग करके आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में न सिर्फ सहभागिता दिखाई, बल्कि पाकिस्तान को 'टेरर स्टेट' घोषित किए जाने की तमाम देशों की मंशा के साथ भी मजबूती से खड़े दिखाई दिए।*

सार्क शिखर सम्मेलन का रद्द होना भारत के उस कड़े फैसले के साथ ही तय हो गया था, जब यह कहा गया कि न तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां जाएंगे, न ही भारत का कोई अधिकारी। सार्क की नियमावली कहती है कि यदि आठ सदस्यीय सार्क से एक भी सदस्य गैरहाजिर होता है, तो यह रद्द हो जाएगा। उरी के बाद भारत की यह पहली बड़ी कूटनीतिक विजय है, जब उसने पाकिस्तान को अलग-थलग करने की कोशिश सफल रही। तीन पड़ोसियों ने जिस तरह इसे मुखर समर्थन दिया, वह आश्वस्त करता है कि पड़ोस की धरती से पनप रही आतंकवाद की बेल को काटने की भविष्य की यह लड़ाई उतनी भी कठिन नहीं है। भारत की इस कूटनीतिक चाल पर पाकिस्तान की प्रतिक्रिया खिसियानी बिल्ली जैसी है। उसने भारत के इस फैसले को दुर्भाग्यपूर्ण भर कहा। इस लड़ाई में भारत के साथ बांग्लादेश, भूटान और अफगानिस्तान के खड़े होने को सिर्फ शुरुआत माना जाना चाहिए और पाकिस्तान के लिए एक चेतावनी भी। सार्क सम्मेलन पर खतरे के बादल तो सिर्फ एक प्रतीक है, दरअसल यह पाकिस्तान की मुश्किलों की शुरुआत है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरह सिंधु जल समझौते पर बड़ी बैठक की, वह भी इस दिशा में एक बड़ा कूटनीतिक कदम माना जा रहा है। माना जा रहा है कि भारत पाकिस्तान को 'मोस्ट फेवर्ड नेशन' यानी तरजीही देश का दर्जा खत्म करने की पहल के साथ वह सब कर देना चाहता है, जो पाकिस्तान को कमजोर करने में सहायक हो। **दरअसल, भारत पाकिस्तान के खिलाफ हर वह असैनिक उपाय आजमा रहा है, जिसके संदेश कड़े हों**। प्रधानमंत्री के वक्तव्य 'खून और पानी दोनों एक साथ नहीं बह सकते' में भी यही स्पष्ट संकेत और संदेश था। ये दो बातें पाकिस्तान को विचलित करने, उसकी चिंता बढ़ाने वाली हैं। भारत हमेशा सौहार्द का पक्षधर रहा है, पाकिस्तान की तमाम कारगुजारियों के बावजूद पिछले महीने गृह मंत्री राजनाथ सिंह का वहां जाना इसी रूप में देखा जाना चाहिए। सार्क सम्मेलन में शामिल न होने का ताजा फैसला मजबूरी में लिया गया फैसला है। इसे पाकिस्तान की हरकतों से उपजे दबाव की तरह से देखा जाना चाहिए। इसके पहले तक सार्क की हर तैयारी में हमारी अब तक की भागीदारी बताती है कि भारत की मंशा हमेशा की तरह इसे सार्थक करने की ही थी। ढाई साल पहले प्रधानमंत्री पद की शपथ लेते समय ही नरेंद्र मोदी ने सार्क देशों के लिए एक विशेष उपग्रह लांच करने की घोषणा की थी, जो बताता है कि उस समय उनके इरादे क्या थे। और अब जो फैसले हो रहे हैं, वे बताते हैं कि दबाव किस तरह के हैं। इसके साथ ही हमारे कई पड़ोसियों ने भी अपने तईं कदम उठाकर पाकिस्तान को आगाह कर दिया है। अब इसके आगे पाकिस्तान को सोचना है।

खटाई में सार्क (जनसत्ता)

सार्क का गठन दक्षिण एशिया में व्यापारिक, वाणिज्यिक और सांस्कृतिक सहयोग को बढ़ावा देने और परस्पर शांति बनाए रखने के मकसद से किया गया था।

को अलग-थलग करने की अगली रणनीति के तहत भारत ने इस्लामाबाद में होने वाले सार्क सम्मेलन में शिरकत करने से इनकार कर दिया है। सार्क के वर्तमान अध्यक्ष देश नेपाल को लिखे पत्र में भारत ने कहा है कि जिस तरह सीमा पार से आतंकवादी गतिविधियों को बढ़ावा दिया जा रहा है, उसमें प्रस्तावित सार्क शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेना उसके लिए संभव नहीं है। भारत के इस फैसले के बाद अफगानिस्तान, बांग्लादेश और भूटान ने भी सार्क शिखर सम्मेलन के बहिष्कार का निर्णय किया है। माना जा रहा है कि आठ सदस्यीय इस संगठन के कुछ और देश बहिष्कार का निर्णय कर सकते हैं।

सार्क घोषणा-पत्र के मुताबिक किसी भी देश के अनुपस्थित रहने पर इसका शिखर सम्मेलन आयोजित नहीं किया जा सकता। पाकिस्तान ने भारत के इस फैसले को दुर्भाग्यपूर्ण करार दिया है। लंबे समय से पाकिस्तान पर आतंकवादी संगठनों के खिलाफ कार्रवाई करने का दबाव डाला जाता रहा है, मगर वह इसे गंभीरता से नहीं लेता। सार्क घोषणा-पत्र में इसके सभी सदस्य देशों ने इस वचनबद्धता पर हस्ताक्षर किए हैं कि वे किसी भी रूप में आतंकवादी गतिविधियों के लिए अपनी जमीन का इस्तेमाल नहीं होने देंगे। मगर पाकिस्तान ने उसे कब का भुला दिया है। इसके अनेक प्रमाण मौजूद हैं कि खासकर भारत के खिलाफ वह आतंकवाद को हथियार के रूप में इस्तेमाल करता आ रहा है। अनेक मौकों पर उसे आतंकवादी हमलों से जुड़े दस्तावेज सौंपे गए, लेकिन उन पर गंभीरता दिखाने के बजाय उन्हें सिरे से खारिज करता रहा है। फिर उसके यहां पनाह पाए आतंकी संगठनों की हरकतों का शिकार केवल भारत नहीं है, बांग्लादेश और अफगानिस्तान में भी पाक समर्थित आतंकवादी संगठनों की तरफ से किए गए हमलों के पुख्ता प्रमाण हैं।

Prepare IAS

सार्क का गठन दक्षिण एशिया में व्यापारिक, वाणिज्यिक और सांस्कृतिक सहयोग को बढ़ावा देने और परस्पर शांति बनाए रखने के मकसद से किया गया था। मगर पाकिस्तान शुरू से इसके घोषणा-पत्र में कही बातों का उल्लंघन करता रहा है। भारत के ताजा फैसले का उस पर शायद ही कोई असर पड़े, पर इससे एक बार फिर दुनिया के सामने उसका पक्ष कमजोर हुआ है। भारत ने व्यापार के लिहाज से उसे विशेष देश का दर्जा दे रखा है, अब वह उसे वापस लेने पर भी विचार कर रहा है। पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति छिपी नहीं है। बेरोजगारी, अशिक्षा और गरीबी के चलते वहां विकास के रास्ते अवरुद्ध हैं। ऐसे में अगर सार्क देश उससे व्यापारिक संबंध तोड़ लेते हैं तो उसकी मुश्किलें और बढ़ेंगी।

G.S.Paper II: *India & its Neighbourhood*: relations

** Kindly refer last week current notes regarding Asylum &refugee

** International refugee law only states that a person needs to be outside his/her own country to seek asylum; it is silent on whether the person needs to be physically present in the territory of the country where s/he hopes to receive asylum or whether s/he can make such an application from a third country. This is a much debated issue in international law and countries have adopted varying policies in this regard.

It is time for a uniform asylum law (The Hindu)

The debate surrounding Brahamdagh Bugti's request for asylum in India has largely focussed on the foreign policy implications. Numerous legal issues deserve consideration.

India stands poised to make one of the most critical decisions with respect to its refugee policy, but without a domestic asylum law and without having signed the UN Refugee Convention of 1951. This has left India without a structured and institutionalised framework for addressing refugee inflows. At the same time, however, the country is known to have a broadly humanitarian approach to asylum, and is bound by both its own constitutional principles and customary international law. As the Home Ministry examines Baloch leader Brahamdagh Bugti's asylum claim, the debate has so far largely centred on the foreign policy implications. There remain, however, numerous legal issues which demand serious consideration.

Unanswered questions

First, the manner in which the current asylum claim has been made raises the question of whether a person can apply for asylum in India from outside the country. Having allowed Mr. Bugti to seek asylum from Switzerland, it is unclear whether India has made an exception in this case or is now open to asylum applications without physical presence within its national borders. This question needs to be settled.

Second, Mr. Bugti claimed in a recent interview that his asylum application to Switzerland was turned down on account of his party being put on a terror watch list by Pakistan. While this could be a politically motivated act by Pakistan, as per international refugee law, this does trigger the need for a prospective asylum country to examine whether Mr. Bugti has committed or been involved in activities referred to as crimes against humanity, war crimes, serious non-political crimes, and so on. A fundamental principle of international refugee law is to not grant

asylum to such persons, as doing so would go against the humanitarian spirit of refugee protection. The civilian character of a refugee populace is paramount, and active combatants are excluded from the same. Therefore, Mr. Bugti's activities as a Baloch leader need to be thoroughly examined.

Third, India's approach towards the larger Baloch refugee community in the future is yet to be addressed. Does India intend to grant asylum to Mr. Bugti alone, or to other Baloch asylum-seekers as well, or on a case-by-case basis? Irrespective of the modality it chooses, the Indian state will have to invest in setting up both a policy mechanism as well as the physical infrastructure for management of this group.

> Indian law does not even mention the term 'refugee', there are no clearly defined rights and duties for refugees.

Finally, if Mr. Bugti is granted asylum in India, what will his legal rights be? In practice, there are multiple approaches towards the different refugee communities, so much so that there isn't even a common form of documentation that is issued to them. The outcome of this is that they have widely disparate access to basic rights. For example, while, which is not widely recognised. There is still no clarity in this regard, and the Baloch would be yet another group of refugees for whom a separate policy would have to be created.

Sri Lankans and Tibetans have government-issued IDs, the vast majority of Afghan and Burmese refugees have only the documentation given to them by the UN

The most pragmatic way to address these legal issues would be for India to adopt a uniform asylum law for all refugee communities. It would allow for the codification of India's best practices with respect to asylum, which would, at the very least, eliminate the need to revisit its historical policies each time it faces a new question of refugee protection. A national asylum law would also reduce the need for parallel mechanisms, and put in place a structured system for asylum management in the future.

अब अगला कदम बलूचिस्तान की आज़ादी हो (Dainik bhaskar)

कुछ माह पूर्व ही इस लेखक ने संभावना जताई थी कि पश्चिम एशिया में नए इजरायल का जन्म हो सकता है। उस लेख की स्याही सूखी भी नहीं कि यह दायित्व भारत के कंधों पर आ पड़ा है। भारतीय सेना ने नियंत्रण-रेखा पर सर्जिकल आॅपरेशन करके सात आतंकी ठिकाने तबाह कर दिए हैं। अब परिस्थितियां कैसा मोड़ लेंगी इस पर अभी कुछ कहना जल्दबाजी होगी। किंतु यह स्पष्ट है कि पाकिस्तान की मस्ती को समाप्त करने के लिए भारत को ही पहल करनी पड़ रही है। पश्चमी भारत और उस के निकट बसे क्षेत्रों में पाकिस्तान जैसी आतंकी गतिविधियां चला रहा है, उससे उसी के अपने क्षेत्रों में हाहाकार मचा हुआ है। बलूचिस्तान

> *सवाल यह है कि बलूचिस्तान का मामला इन दिनों ही क्यों सर उठा रहा है? जवाब यह है कि भारत का ईरान को भरोसे में लेकर चाबहार बंदरगाह विकसित करना। इससे पाकिस्तान और चीन दोनों ही बेचैन हैं। भारत यदि इस बंदरगाह को अपना आधार बना लेता है तो दोनों उसके निशाने पर आ जाते हैं। ईरान के समर्थन से अमेरिका भी चौंक गया है, क्योंकि यही वह क्षेत्र है जहां रूस की सीमाएं मिलती हैं। रूस भारत को समर्थन देकर अपनी नेवी से पाक और चीन के हौसले पस्त कर सकता है। रूस-भारत मैत्री इन शक्तियों के लिए बड़ी चुनौती होगी, इसलिए इन दिनों पाकिस्तान रूस के निकट जाने के प्रयास में लगा है।*

Prepare IAS

और सिंध भी उसकी चपेट में हैं। एेसे में भारत के पास इसके अलावा कोई विकल्प नहीं है कि अपने यहां शांति कायम करने के लए पहले सिंध-बलूचिस्तान में शांति के प्रयास करे।

**18वीं शताब्दी में बलूचिस्तान के शासक नसीर खान बलूच को नूरी नसीर कहा जाता था। उसकी सार्वभौम सरकार पर 1839 में ब्रिटिश सरकार ने हमला किया, लेकिन कलात तक अंग्रेज सेना पहुंचने के बाद बलूच जनता हार गई। उल्लेखनीय है कि तब तक सेना और उसके सरदार सभी हिंदू थे। महत्वपूर्ण नगर मकरान और लासबेला उन के हाथों से निकल गए। तब यह हिंदू बहुल प्रदेश था। जब देश में स्वतंत्रता की हवा चली तो 11 अगस्त 1947 को यह भाग ब्रिटिश सत्ता से स्वतंत्र हो गया। उस समय वहां की जनता और तत्कालीन शासन ने उसे स्वतंत्र देश की मान्यता दी। भारत की आजादी के साथ ही सितंबर 1947 में जिस प्रकार पाकिस्तान ने कश्मीर पर आक्रमण किया, उसी प्रकार 27 मार्च 1948 को बलूचिस्तान पर पाकिस्तान ने हमला करके उसकी स्वतंत्रता पर सवालिया निशान लगा दिया।1948 में प्रिंस अब्दुल करीम खान के छोटे भाई ने प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की बागडोर हाथों में ले ली। 1996 से वहां पाकिस्तानियों की घुसपैठ बढ़ी। उस समय नवाब रोज खान ने बलूच लिबरेशन आर्मी तैयार कर ली। उन्होंने स्वतंत्र होने का बड़ा प्रयास किया, लेकिन पाकिस्तान का शिकंजा कसता चला गया।

पाकिस्तान का सब से बड़ा भौगोलिक क्षेत्र बलूचिस्तान है, इसलिए जब तक वहां शांति स्थापित नहीं होती तब तक भारत भी सुख-चैन से नहीं रह सकता। बलूचिस्तान पाकिस्तान के अत्याचारों से बुरी तरह त्रस्त है। वह चाहता है कि भारत उसे आजाद कराने में सहायता करे, लेकिन भारत हस्तक्षेप करने में हिचकिचाता रहा है। किंतु ऐसा लगता है कि पाकिस्तान ने इन दिनों भारत से टकराने का मन बना लिया है, इसलिए भारत के लिए स्वर्णिम अवसर है कि जब वह बलूच जता की सहायता कर उसे मुक्ति दिला दे। भारत और बलूच जनता मिलकर पाकिस्तान को पाठ पढ़ाएंगे तो इस क्षेत्र में स्थायी शांति कायम हो सकेगी। निकट भविष्य में पाकिस्तान में बांग्लादेश दोहराया गया तो दुनिया को आश्चर्य नहीं होगा। ऐसा हुआ तो मध्य एशिया की शांति के लिए एक और इजरायल बनाना पड़ेगा।

माओ के चीन ने 1962 में भारत पर आक्रमण कर उस के लद्दाख एवं अक्साई चीन वाले क्षेत्र पर कब्जा कर लिया। इतना ही नहीं बाल्टिस्तान और गिलगित जैसे क्षेत्रों को भी कब्जे में ले लिया। पाक ने अपना माल समझकर सारा क्षेत्र चीन के हवाले कर दिया। नतीजतन चीन ने अक्साई चीन से गिलगित वाया बाल्टिस्तान होकर अपनी सेना अफगानिस्तान तक पहुंचाने का षड्यंत्र रचा। **अब चीन का प्रयास है कि वह भारत के समुद्री किनारे तक येन केन प्रकारेण पहुंच जाए। चीन-पाकिस्तान आर्थिक कॉरिडोर इसी का नतीजा है।** इतना ही नहीं चीन ने हिमालय में रेल लाइनें स्थापित कर ली हैं। कुल-मिलाकर बलूचिस्तान के सहारे चीन ने भारत के पश्चिमोत्तर भागों तक अपनी पहुंच बना ली है। हालांकि, पाकिस्तान जानता है कि चीन का प्रसार उस के लिए अत्यंत जोखिम भरा है। यदि आज भारत चीन के निशाने पर है तो कल पाकिस्तान की बारी है, लेकिन उसकी एक ही नीति है 'मैं तो मरूं सो मरूं लेकिन तुझे विधवा करूं।' इस बीच पाकिस्तान ने जिस प्रकार बांग्लादेशियों को निर्वासित कर उन्हें दर-दर भटकने पर मजबूर किया था, वही रणनीति अपनाकर अब वह बलूचों को उनके प्रदेशों से निकाल देना चाहता है। वह इस क्षेत्र में पंजाब के कट्टर सुन्नियों को लाकर बसाने के प्रयास में जुटा है।

प्रधानमंत्री मोदी ने स्वतंत्रता दिवस के भाषण में उन सारे क्षेत्रों के नामों का उल्लेख करके देश और दुनिया को याद दिला दिया कि पाकिस्तान ने किस प्रकार अपनी हड़प नीति से क्षेत्र को अस्थिर बना रखा है। बांग्लादेश बन जाने के बाद भी पाक नेताओं की लार टपकना बंद नहीं हुई है, इसलिए भारत को एक बार फिर उसका दिमाग ठिकाने पर लाने की कार्रवाई करना अनिवार्य हो गया। पाकिस्तान का यह दिवा स्वप्न है कि वह आसपास के देश हड़पकर दक्षिण-पूर्वी एशिया की ताकत बन जाए, लेकिन अंतरराष्ट्रीय कूटनीतिज्ञों को आशंका है कि कहीं पाकिस्तान इस्लामाबाद की सीमाओं तक मर्यादित न रह जाए। ऐसा हुआ तो इजरायल की तरह एशिया में एक और इजरायल बन जाएगा, जो इस्लाम के नाम पर राजनीति करने वालों को हमेशा उनकी औकात दिखाने में कोई कसर नहीं छोड़ेगा। अब वह समय निकट आ गया है जब पाकिस्तान टूटेगा नहीं बल्कि दुनिया के मानचित्र से ही विदा हो जाएगा।

Prepare IAS

G.S. Paper II: Structure, organization & functioning of the Executive & the Judiciary

** फोर्थ जजेज मामले (सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स-ऑन-रेकार्ड बनाम संघ) में गत वर्ष अक्टूबर में सर्वोच्च अदालत ने संविधान के 99वें संशोधन को निरस्त कर दिया, जिसके द्वारा राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग का गठन किया गया था।

** अदालत ने स्वीकार किया कॉलेजियम की कार्यपद्धति में कई कमियां हैं और सरकार से प्रक्रिया की विवरणिका बनाने को कहा। बात इसी पर अटक गई, क्योंकि सरकार राष्ट्रीय सुरक्षा के आधार पर किसी भी नियुक्ति को वीटो करने का अधिकार अपने पास रखना चाहती है, जो शीर्ष न्यायालय को मंजूर नहीं है।

**। फर्स्ट जजेज मामले (एसपी गुप्ता बनाम संघ) में 1981 में अदालत ने कहा कि चूंकि कार्यपालिका जनता के प्रति जवाबदेह है और न्यायपालिका की ऐसी कोई जवाबदेही नहीं है, इसलिए नियुक्ति का अधिकार कार्यपालिका के पास होना चाहिए।

** 1993 में सेकंड जजेज मामले में इस निर्णय को पलटते हुए उच्चतम न्यायालय की एक संविधान पीठ ने कहा कि संविधान का उद्देश्य योग्य एवं ईमानदार न्यायाधीशों की नियुक्ति करना है। अदालत के अनुसार, न्यायाधीश ही किसी वकील की योग्यता एवं निष्ठा की परख कर सकता है। विधायिका के पास वकीलों की योग्यता परखने का कोई जरिया नहीं है और अनुच्छेद 121 एवं 211 के तहत न्यायाधीशों के चरित्र पर संसद या विधानमंडल में कोई बहस नहीं हो सकती है। इसी तर्क पर न्यायालय ने न्यायाधीशों की नियुक्ति का अधिकार कार्यपालिका से छीनकर अपने हाथों में ले लिया।

कॉलेजियम पर न्यायमूर्ति का सवाल (दैनिक जागरण)

उच्च न्यायपालिका में न्यायाधीशों की नियुक्ति को लेकर जो टकराव की स्थिति उच्चतम न्यायालय तथा केंद्र सरकार के बीच उत्पन्न हो गई है, वैसा टकराव हाल के दशकों में देखने को नहीं मिला है। प्रधान न्यायाधीश टी एस ठाकुर न्यायाधीशों की नियुक्ति नहीं किए जाने को लेकर सरकार पर प्रहार करने का कोई मौका हाथ से जाने नहीं देते। दूसरी ओर केंद्र सरकार भी उच्च न्यायपालिका में न्यायाधीशों की नियुक्ति का अधिकार पूरी तरह से न्यायपालिका के हाथों छोड़ना नहीं चाहती। परंतु अदालत ने इतना स्वीकार किया कॉलेजियम की कार्यपद्धति में कई कमियां हैं और सरकार से प्रक्रिया की विवरणिका बनाने को कहा। बात इसी पर अटक गई, क्योंकि सरकार राष्ट्रीय सुरक्षा के आधार पर किसी भी नियुक्ति को वीटो करने का अधिकार अपने पास रखना चाहती है, जो शीर्ष न्यायालय को मंजूर नहीं है।उच्चतम न्यायालय ने व्याख्या के जरिये कॉलेजियम व्यवस्था थोपी है, जिसका संविधान में कोई जिक्र नहीं है.

कॉलेजियम की कार्यप्रणाली पर अक्सर सवाल उठते रहे हैं। परंतु इस बार आवाज अंदर से आई है। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश एवं कॉलेजियम के सदस्य न्यायमूर्ति जे चेलामेश्वर ने आरोप लगाया है कि कॉलेजियम के कामकाज में पारदर्शिता नहीं है और वह भविष्य में कॉलेजियम की बैठकों में भाग नहीं लेंगे। सवाल यह नहीं है कि नियुक्ति कौन करता है या उसकी प्रक्रिया क्या है। सवाल यह है कि क्या नियुक्ति के बाद उसे पूर्ण सुरक्षा मिलती है। यदि हां, तो नियुक्ति का अधिकार किसके पास है, यह अहम नहीं है। इसलिए न्यायमूर्ति चेलामेश्वर ने फोर्थ जजेज मामले में संविधान पीठ के अन्य चार न्यायाधीशों के साथ असहमति जताते हुए राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग के गठन को सही माना। उन्होंने मेरी पुस्तक जस्टिस, जूडोक्रेसी ऐंड डेमोक्रेसी इन इंडिया से एक अंश उद्धृत किया, जिसमें मैंने लिखा है कि राजनीति में सक्रिय कई अधिवक्ताओं को जज बनया गया। केएस हेगड़े तथा टकेचंद तो राज्यसभा सांसद थे, जब उन्हें उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनाया गया। परंतु जस्टिस हेगड़े इतने निष्पक्ष रहे कि उन्हें उन्हीं की कांग्रेस सरकार ने भारत का प्रधान न्यायाधीश नहीं बनने दिया। न्यायमूर्ति वी आर कृष्ण अय्यर पहले केरल सरकार में मंत्री थे, और उन्हें सुप्रीम कोर्ट का जज बनाए जाने का काफी विरोध था, पर वह एक आदर्श जज साबित हुए।

Share IAS

Isro sets sights high in global space race (Asian Age)

To see our nation progress from the unforgettable vignette of its early space programme, reflected in a rocket being carried on the back of a bicycle in Thumba, Kerala, to where we are now is heart-warming

G.S. Paper III:
Awareness in fields of IT, Space, Computers, Robotics, Nanotechnology, Biotechnology

** ISRO has successfully launched PSLV-C-35 injecting India's SCATSAT-1 in orbit.

** According to ISRO, SCATSAT-1 is a continuity mission for Oceansat-2 scatterometer to provide wind vector data products for weather forecasting, cyclone detection and tracking services to the users.

In flawlessly executing its two-in-one mission of two different orbits in a single mission, India's elite space agency is all set to become an even bigger player in the international satellite launch business. With 79 foreign satellite launches on its books, Isro is already a virtual Indian multinational in marketing launches. It is setting its sights even higher, trying to establish a manufacturing base in association with industry to make very effective 3D and 3DR weather satellites for foreign countries after meeting India's requirements. The proven stop-start capability of the rocket attained in Monday's longish 135-minute flight record is what will give the Polar Satellite Launch Vehicle (PSLV) an edge in space commerce, besides its safety record of 33 consecutive successful missions. It is justifiable then for Indians to take pride in Isro's exploits, starting with Prime Minister Narendra Modi, who is an unabashed fan of our scientists who made this possible. To adapt an old homily, the sky is not even the limit for Isro now.

The European Space Agency's Vega rocket is said to have accomplished this complicated burn tech manoeuvre first, and others will join the race from the American private sector. Launch players like Ellon Musk and new economy czars like Jeff Bezos and Mark Zuckerberg are fascinated with these cutting-edge technologies in space research and engineering, and there will be no dearth of business in space. Their pockets are deep enough not to let an early disaster like the recent SpaceX Falcon 9 rocket exploding on the launch pad deter them. But what gives Isro and India the commercial advantage is the low cost of operations. Achieved on a shoestring budget, the Mangalyaan orbiter shook up the space community with its economy and endurance as the two-year-old probe has lived on well beyond its projected life and is still beaming back useful data.

In its conquest of space technology, Isro has gone far as an international player, its commercial arm Antrix having shown a turnover of Rs 1,790 crores in the current year. What this has done is to elevate India's image from being the world's back office — which business does of course bring in very valuable revenue in foreign exchange — to a pioneer in complex space engineering. Its

successful demonstration last month of the hypersonic air-breathing dual mode ramjet engine (known as Scarmjet), using atmospheric oxygen in a part of its journey, saw it pursuing a most futuristic concept, revealing its ambition to be a premier space-faring agency. To see our nation progress from the unforgettable vignette of its early space programme, reflected in a rocket being carried on the back of a bicycle in Thumba, Kerala, to where we are now is heart-warming.

देश में बेरोजगारी बढ़ी, पहुंची पांच साल के उच्च स्तर पर (बीबीसी हिंदी)

केंद्र सरकार के रोजगार सृजन पर जोर के बावजूद देश में बेरोजगारों की संख्या बढ़ रही है। श्रम ब्यूरो की रिपोर्ट के अनुसार देश की बेरोजगारी दर 2015-16 में पांच प्रतिशत पर पहुंच गई जो पांच साल का उच्च स्तर है। महिलाओं के मामले में बेरोजारी दर उल्लेखनीय रूप से 8.7 प्रतिशत के उच्च स्तर पर जबकि पुरुषों के संदर्भ में यह 4.3 प्रतिशत रही। यह आंकड़ा केंद्र की भाजपा शासित सरकार के लिए खतरे की घंटी हो सकती है जिसने देश में समावेशी वृद्धि के लिए रोजगार सृजित करने को लेकर 'मेक इन इंडिया' जैसे कई कदम उठाए हैं।

G.S. Paper III: Indian Economy & issues relating to planning, mobilization of resources, growth, development & employment.

** अखिल भारतीय स्तर पर पांचवें सालाना रोजगार-बेरोजगारी सर्वे के अनुसार करीब 77 प्रतिशत परिवारों के पास कोई नियमित आय या वेतनभोगी व्यक्ति नहीं है।

इसके अनुसार यूपीएस (यूजुअल प्रिंसिपल स्टेटस) रुख के तहत अखिल भारतीय स्तर पर बेरोजगारी दर पांच प्रतिशत अनुमानित है। यूपीएस रुख के तहत बेरोजगारी दर के आकलन के लिए संदर्भ अवधि 365 दिन का उपयोग किया जाता है। श्रम ब्यूरो के अनुसार 2013-14 में बेरोजगारी दर 4.9 प्रतिशत, 2012-13 में 4.7 प्रतिशत, 2011-12 में 3.8 प्रतिशत तथा 2009-10 में 9.3 प्रतिशत रही। वर्ष 2014-15 के लिए इस प्रकार की रिपोर्ट जारी नहीं की गई। रिपोर्ट के मुताबिक, 'यूपीएस रुख के तहत ग्रामीण क्षेत्र में बेरोजगारी दर 5.1 प्रतिशत जबकि शहरी क्षेत्र में 4.9 प्रतिशत थी।' पुरुषों की तुलना में महिलाओं में बेरोजगारी दर सबसे ऊंची है। महिलाओं में बेरोजगारी दर 8.7 प्रतिशत आंकी गई है जबकि पुरुषों में 4.3 प्रतिशत थी।

शहरी क्षेत्रों में महिलाओं में बेरोजगारी दर 12.1 प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया गया है, वहीं पुरूषों में 3.3 प्रतिशत तथा किन्नरों में यह 10.3 प्रतिशत रही। सर्वे सभी राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों में अप्रैल 2015 से दिसंबर 2015 के दौरान किए गए। इसमें कुल 1,56,563 परिवारों को शामिल किया। इसमें 88,783 ग्रामीण क्षेत्र में जबकि 67,780 शहरी क्षेत्र के हैं। सर्वे में राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों में त्रिपुरा (19.7 प्रतिशत) सबसे ऊपर है। उसके बाद क्रमश: सिक्किम (18.1 प्रतिशत), लक्षद्वीप (16.1 प्रतिशत), अंडमान निकोबार द्वीप (12.7 प्रतिशत), केरल (12.5 प्रतिशत) तथा हिमाचल प्रदेश (10.6 प्रतिशत) का स्थान है।

PrepareIAS

विवादास्पद 9/11 विधेयक पर ओबामा का वीटो ख़ारिज

अमरीकी कांग्रेस ने बहुमत से राष्ट्रपति बराक ओबामा द्वारा 9/11 विधेयक पर लगाए गए वीटो को दरकिनार करने के पक्ष में मतदान किया है.राष्ट्रपति ओबामा के आठ वर्षों के शासनकाल में यह पहला मौका है जब उनके वीटो को संसद ने दरकिनार किया है. बराक ओबामा ने कहा है कि इस विधेयक पर उनके वीटो को ख़ारिज करके संसद के फैसले ने एक ख़तरनाक मिसाल कायम की है.

G.S. Paper II: Effect of policies & politics of developed & developing countries.

** आतंकवाद के पोषण करने वालों के खिलाफ न्याय अधिनियम (जास्टा) के मुताबिक ग्यारह सितंबर हमलों के पीड़ितों परिवारों को अधिकार मिला था कि वो सऊदी सरकार के खिलाफ मुकदमा दायर कर सकते हैं.

** इस विधेयक के पारित होने के बाद इससे अमरीकी सुरक्षा बलों और विदेशों में काम कर रहे अमरीकी लोगों पर संभावित कानूनी कार्रवाई संभव हो जाएगी.

महत्वपूर्ण है कि ओबामा ने उस विधेयक पर वीटो किया था जिसके मुताबिक ग्यारह सितंबर हमलों के पीड़ितों परिवारों को अधिकार मिला था कि वो सऊदी सरकार के खिलाफ मुकदमा दायर कर सकते हैं.

ओबामा के वीटो को दरकिनार करने के पक्ष में 97 मत पड़े जबकि वीटो के पक्ष में केवल एक ही वोट पड़ा.

आतंकवाद के पोषण करने वालों के खिलाफ न्याय अधिनियम (जास्टा) नाम वाले बिल के खिलाफ अमरीकी राष्ट्रपति ने कड़ी मेहनत की थी.

ओबामा ने रिपब्लिकन और डेमोक्रेटिक सीनेट नेताओं को भेजे गए पत्र में कहा था कि कानून के रूप में जास्टा लागू करना अमरीका के राष्ट्रीय हितों के लिए नुकसानदेह होगा.

ओबामा ने कहा कि इस बिल को पारित करने के संसद के फैसले से राष्ट्रपति के संप्रभुता के अधिकार की अवधारणा खत्म हो जाएगी.

डेमोक्रेटिक पार्टी के सांसद चक स्कमर ने कहा है कि ये महत्वपूर्ण है कि पीड़ितों के परिजनों को न्याय पाने की अनुमति मिल सके, भले ही इसके कारण राजनयिक परेशानियों होती हों.

ओबामा ने अपने राष्ट्रपति के कार्यकाल में अभी तक 12 बार वीटो का इस्तेमाल किया है लेकिन ये पहला मौका है जब उनकी वीटो शक्ति को दरकिनार नहीं किया गया है.

PrepareIAS

निर्गुट की विरासत (जनसत्ता)

(G.S. Paper II: Bilateral, regional & global groupings & agreements involving India &/or affecting Indian interests)

** NAM पहला सम्मेलन 1961 में बेलग्रेद में हुआ था। इसकी नींव डालने वालों में भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, यूगोस्लाविया के प्रथम राष्ट्रपति सुकर्णो, मिस्र के दूसरे राष्ट्रपति गमाल अब्देल नासिर और यूगोस्लाविया के तत्कालीन राष्ट्रपति टीटो प्रमुख थे।

जब गुटनिरपेक्ष आंदोलन की स्थापना हुई थी, दुनिया मोटे तौर पर दो खेमों में विभाजित थी। एक खेमा अमेरिका का था, और दूसरा सोवियत संघ का। गुटनिरपेक्ष या निर्गुट आंदोलन का बुनियादी मकसद इन दो खेमों से तटस्थ रहना और विश्व को शीतयुद्ध से मुक्ति दिलाना था। दोनों खेमों के बरक्स इसने विकासशील देशों को एक बड़ा मंच मुहैया कराया और एक कठिन समय में विश्व की ऐतिहासिक सेवा की। गुटनिरपेक्षता की उनकी अवधारणा रंग लाई और इस आंदोलन में शामिल होने वाले देशों की संख्या बढ़ती गई। खासकर यह विकासशील देशों का सबसे बड़ा मंच हो गया।

लेकिन सोवियत संघ के विघटन के बाद से गुटनिरपेक्ष आंदोलन की सार्थकता या प्रासंगिकता पर सवाल उठते रहे हैं। कहा जाता रहा है कि शीतयुद्ध की समाप्ति के बाद इसका क्या औचित्य रह गया है। यह पहला मौका है जब निर्गुट सम्मेलन में भारत केप्रधानमंत्री ने शिरकत नहीं की। इस मौके पर देश का प्रतिनिधित्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी ने किया। कहीं भारत के मौजूदा राजनीतिक नेतृत्व के मन में भी तो इस समूह की अहमियत को लेकर शंका नहीं है? या, निर्गुट सम्मेलन में हिस्सा लेने प्रधानमंत्री इसलिए नहीं गए कि भारत की विदेश नीति में अब अमेरिका के करीब आने की चाहत बहुत बढ़ गई है? यों, यह रुझान यूपीए सरकार के समय ही शुरू हो गया था, जब उसने एटमी समझौते के लिए वाम दलों के समर्थन की कुर्बानी देना मंजूर किया। बहरहाल, गुटनिरपेक्ष खेमा अपनी धार भले खो चुका हो, सदस्य संख्या के लिहाज से यह अब भी एक बड़ा समूह है जिसमें एक सौ बीस देश साझीदार हैं।

निर्गुट आंदोलन की स्थापना के पीछे इरादा शीतयुद्ध से त्राण पाना था। जाहिर है, इसमें विश्व शांति का व्यापकतर उद्देश्य निहित था। आज आतंकवाद के खिलाफ अंतरराष्ट्रीय एकजुटता को प्रशस्त कर निर्गुट आंदोलन अपनी विरासत को आगे बढ़ा सकता है। वेनेजुएला के पोर्लामर में सत्रहवें गुटनिरपेक्ष सम्मेलन के पूर्ण अधिवेशन को संबोधित करते हुए भारत के उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी ने जो कुछ कहा वह प्रकारांतर से निर्गुट समूह को नए सिरे से प्रासंगिक बनाए जाने की तरफ इशारा करना ही था। उन्होंने कहा कि अब वक्त आ गया है कि हमारा आंदोलन आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में ठोस कदम उठाने की जरूरत को रेखांकित करे। उपराष्ट्रपति की यह टिप्पणी ऐसे वक्त आई है जब पिछले दिनों प्रधानमंत्री जी-20, ब्रिक्स और आसियान एवं पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन जैसे अंतरराष्ट्रीय मंचों पर आतंकवाद को लेकर भारत की चिंता जाहिर कर चुके थे।

Prepare IAS

What were the intifadas?

In UNGA Nawaz Sharif used the term Kashmiri intifada and in return Indian officer said Pakistan as IVY League of terriorism. Here is explanation of both terms.

The intifadas were two Palestinian uprisings against Israel, the first in the late 1980s and the second in the early 2000s. The intifadas had a dramatic effect on Israeli-Palestinian relations; the second, in particular, is widely seen as marking the end of the 1990s era negotiating process and ushering in a new, darker era in Israeli-Palestinian relations.

The first intifada was a largely spontaneous series of Palestinian demonstrations, nonviolent actions like mass boycotts and Palestinians refusing to work jobs in Israel, and attacks (using rocks, Molotov cocktails, and occasionally firearms) on Israelis. Palestinian fatalities dramatically outpaced Israeli ones, as the Israeli military responded to the protests and attacks with heavy force.

The second, and far bloodier, intifada grew out of the collapse of the peace process in 2000. Negotiations between Israeli Prime Minister Ehud Barak and PLO Chairman Yasser Arafat broke down, and the intifada began shortly afterwards. Typically, Israelis blame a conscious decision by Arafat to turn to violence for the intifada's onset, while Palestinians point to an intentionally provocative visit to the contested Temple Mount by Israeli politician (and soon to be Prime Minister) Ariel Sharon. While both Arafat and Sharon played some part, the central cause was likely a basic mistrust between the two sides that made war inevitable after peace talks broke down.

The spark that lit this powder keg was a series of Palestinian demonstrations that Israeli soldiers fired on. Palestinian militants subsequently escalated to broader violence, and the PA refused to rein them in.

The Ivy League is a collegiate athletic conference comprising sports teams from eight private institutions of higher education in the Northeastern United States. The conference name is also commonly used to refer to those eight schools as a group. The eight institutions are Brown University, Columbia University, Cornell University, Dartmouth College, Harvard University, the University of Pennsylvania, Princeton University, and Yale University. The term Ivy League has connotations of academic excellence, selectivity in admissions, and social elitism.

PaperII : Issues relating to development and management of Social Sector/Services relating to Health, Education, Human Resources, issues relating to poverty and hunger.

**145 districts have TFR of more than or equal to 3 (56% of the 261 districts in the 7 High Focus States), and are home to 28% of India's population, which is about 33 crore.

Mission Parivar Vikas to be launched to push contraceptive use (PIB)

The government will soon launch Mission Parivar Vikas to improve family planning services in seven states where the combined total fertility rate (TFR), or the number of children a woman has in her lifetime) constitutes 44% of the country's population.

- The main objective of 'Mission Parivas Vikas is to accelerate access to high quality family planning choices based on information, reliable services and supplies within a rights-based framework.
- The Union ministry of health and family welfare will launch the programme in 145 high-focus districts of Uttar Pradesh, Bihar, Rajasthan, Madhya Pradesh, Chhattisgarh, Jharkhand and Assam.
- These districts were identified based on their total fertility rate and sterilization performance among other measures taken for family planning, for immediate, special and accelerated efforts.

- The target of the government is to reach the replacement level fertility goals of 2.1 by the year 2025.
- The key strategic focus of this initiative will be on improving access to contraceptives through delivering assured services, dovetailing with new promotional schemes, ensuring commodity security, building capacity (service providers), creating an enabling environment along with close monitoring and implementation.

Short Notes for Pre. & Mains from this week:

1- MERCOSUR

Mercosur is a sub-regional bloc. Its full members are Argentina, Brazil, Paraguay, Uruguay and Venezuela. Its associate countries are Bolivia, Chile, Peru, Colombia, Ecuador and Suriname. The Mercusor trading bloc was established in 1991 and negotiations with the EU originally started in 2010 with a number of 'rounds' of negotiations, which have the overall aim to agree a trade deal between the two blocs to allow easier trading of goods and services as well as government procurement and intellectual property and technical barriers to trade.

2- Most Favoured Nation (MFN)

According to the MFN principle of the WTO's General Agreement on Tariffs and Trade (GATT) — to which India is a signatory/contracting party — each of the WTO member countries should "treat all the other members equally as 'most-favoured' trading partners."According to the WTO, though the term 'MFN' "suggests special treatment, it actually means non-discrimination."

The MFN status was accorded in 1996 as per India's commitments as a member of the World Trade Organization (WTO).

3-